

(ग) क्या इस खर्च के हिसाब से डाक सामग्री पर भी दाम बढ़ेंगे और तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी. नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पत्रों के वितरण में विलम्ब

862. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में डाक का वितरण कितनी बार होता है और पत्र को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में औसतन कितना समय लगता है ;

(क) क्या यह सच है कि जो पत्र अपने गन्तव्य स्थान पर अधिक से अधिक तीन दिन में पहुंच जाना चाहिए वह 15-20 दिनों में भी नहीं पहुंचता ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या विदेशों के लिए पत्रों की निकासी प्रतिदिन की जाती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस पद्धति में कब तक सुधार किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाक एक दिन में अधिक से अधिक तीन बार बांटी जाती है। जहां तक संभव होता है डाक का वितरण जल्दी ही कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) पत्र सामान्यतया 1 से 3 दिनों में अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। परन्तु कभी-कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो विभाग के नियंत्रण

से बाहर होती हैं और जिनके फलस्वरूप डाक में विलम्ब हो जाता है। यह विलम्ब सामान्यतया हवाई जहाजों अथवा बसों के देरी से चलने के कारण होता है। कभी-कभी डाक में कुछ स्थानीय आंदोलनों के कारण भी विलम्ब हो जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Introduction of Bill on Electoral Reforms

*863. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to reply given to U.S.Q. No. 5754 on 5.4.83 regarding electoral reforms and state :

(a) whether it is proposed to bring forward any Bill for Electoral Reforms before Parliament during the present Budget Session or even in the coming Autumn Session ;

(b) if so, details thereabout ; and

(c) if not, reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) to (c) The various proposals relating to electoral reforms are under consideration and in view of the nature of the proposals it would not be possible to indicate any time limit as to when final decisions would be taken and necessary Bill brought forward before the Parliament as the proposals would have to be considered by the Cabinet Committee on Electoral Reforms and would involve discussions with political parties and where necessary, with State Governments also.

Import of Chemicals

*864. SHRI GULSHER AHMED : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large